



# राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, सोमवार, १५ जनवरी, १९९६/ २५ पौष, १९१७

हिमाचल प्रदेश सरकार

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला-४, १५ जनवरी, १९९६

संख्या १-३/९६-वि०स०.—हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, १९७३ के नियम १३५ के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश जनरल सेल्ज टैक्स (संशोधन) विधेयक, १९९६ (१९९६

का विधेयक संख्यांक 2) जो दिनांक 15 जनवरी, 1996 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्वसाधारण की सूचनार्थ असाधारण राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

हस्ताक्षरित/-  
सचिव,  
हिमाचल प्रदेश विधान सभा।

1996 का विधेयक संख्यांक 2.

## हिमाचल प्रदेश जनरल सेल्ज टैक्स (संशोधन) विधेयक, 1996

(विधान सभा में यथा पुरः स्थापित)

हिमाचल प्रदेश जनरल सेल्ज टैक्स ऐक्ट, 1968 (1968 का 24) का और संशोधन करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के छियालीसवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश जनरल सेल्ज टैक्स (संशोधन) ऐक्ट, 1996 है।

संक्षिप्त  
नाम और  
प्रारम्भ।

(2) यह 15 नवम्बर, 1995 से प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

2. हिमाचल प्रदेश जनरल सेल्ज टैक्स ऐक्ट, 1968 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 6 की उप-धारा (1) के प्रथम परन्तुक में, "item 25 and 34" शब्दों और अंकों के स्थान पर "items 25, 34 and 36" शब्द, अंक और चिह्न रखे जाएंगे।

धारा 6 का  
संशोधन।

3. मूल अधिनियम की अनुसूची "A" में;—

अनुसूची  
"A" का  
संशोधन।

(क) मद 31 में, "per piece" शब्दों के पश्चात् "but not including polythene bags" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे; और

(ख) मद 35 के पश्चात्, निम्नलिखित मद जोड़ी जाएगी, अर्थात्:—

### 36. "Polythene bags"

1995 का 4

4. (1) हिमाचल प्रदेश जनरल सेल्ज टैक्स (संशोधन) अध्यादेश, 1995 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

निरसन और  
व्यावृत्ति।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, निरसित अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई समझी जाएगी, मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी तात्त्विक समय पर प्रवृत्त थे।

## उद्देश्यों और कारणों का कथन

पर्यावरण के प्रदूषण का बढ़ता हुआ खतरा दिन प्रतिदिन अत्यन्त चिन्ता का विषय बनता जा रहा है। इस पर प्रभावी नियन्त्रण रखने के लिए, पोलिथीन थैलियों के विक्रय कर की दर में 8% से 30% की मारत बढ़ोतरी करके इसके उपयोग को हतोत्साहित करने के लिए और जीव अनाशित पोलिथीन थैलियों के बदले में, जो पर्यावरण के प्रदूषण में वृद्धि का स्रोत है, जीव नाशित थैलियों के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करने का विनिश्चय किया गया था। इसलिए तत्काल कार्रवाई करना आवश्यक हो गया था।

क्योंकि विधान सभा सत्र में नहीं थी और हिमाचल प्रदेश जनरल सेल्ज टैक्स ऐक्ट, 1968 में शीघ्र संशोधन किया जाना था, इसलिए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल द्वारा 13 नवम्बर, 1995 को भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) के अधीन हिमाचल प्रदेश जनरल सेल्ज टैक्स (संशोधन) अध्यादेश, 1995 प्रख्यापित किया गया था, जो 15 नवम्बर, 1995 को राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण) में प्रकाशित किया गया था। उक्त अध्यादेश को अब नियमित अधिनियमिति द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना अपेक्षित है।

यह विधेयक उपर्युक्त अध्यादेश को बिना उपान्तरण के प्रतिस्थापित करने के लिए है।

सन्त राम,  
प्रभारी मन्त्री।

शिमला :

15 जनवरी, 1996.

## वित्तीय ज्ञापन

विधेयक का खण्ड 2 और 3, पोलिथीन की थैलियों पर विक्रय कर के दर को 8 प्रतिशत से बढ़ाकर 30 प्रतिशत करने का उपबन्ध करता है। इस बढ़ोतरी के परिणामस्वरूप, राजकोष में यद्यपि कुछ आय प्रोद्भूत होगी, तथापि पोलिथीन थैलियों के उपयोग को हतोत्साहित करने की राज्य की नीति के कारण, राजकोष में प्रतिवर्ष पांच लाख रुपये की हानि होगी।

## प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

—शून्य—

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल की सिफारिशें

[फाईल संख्या ई0 एक्स0 एन0-सी0 (9)2/90-खण्ड-V]

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश जनरल सेल्ज टैक्स (संशोधन) विधेयक, 1996 की विषय-वस्तु के बारे में सूचित किए जाने के पश्चात्, भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन विधेयक को विधान सभा में पुरःस्थापित करने और उस पर विचार करने की सिफारिश करती है।

**AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT**

**Bill No. 2 of 1996.**

**THE HIMACHAL PRADESH GENERAL SALES TAX (AMENDMENT)  
BILL, 1996**

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

**BILL**

*further to amend the Himachal Pradesh General Sales Tax Act, 1968 (Act No. 24 of 1968).*

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Forty-sixth Year of the Republic of India, as follows:—

1. (1) This Act may be called the Himachal Pradesh General Sales Tax (Amendment) Act, 1996.

Short title and commencement

(2) It shall and shall be deemed to have come into force on the 15th day of November, 1995.

24 of 1968

2. In section 6 of the Himachal Pradesh General Sales Tax Act, 1968 (hereinafter called the principal Act), in sub-section (1), in the first proviso, for the words and figures "items 25 and 34", the words, figures and sign "items 25, 34 and 36" shall be substituted.

Amendment of section 6.

3. In Schedule 'A' of the principal Act,—

(a) in item 31, after the words "per piece", the words "but not including polythene bags" shall be inserted; and

(b) after item 35, the following item shall be added, namely :—

"36. Polythene bags".

Amendment of Schedule 'A'

4 of 1995

4. (1) The Himachal Pradesh General Sales Tax (Amendment) Ordinance, 1995, is hereby repealed.

Repeal and savings.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the repealed Ordinance, shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act, as amended by this Act, as if the provisions of this Act were in force at all material times.

## STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Menace of increasing pollution of environment is becoming a matter of great concern day-by-day and to have an effective check over it, it was decided to encourage the use of bio-degradable substitutes, for non-bio-degradable polythene bags which are, an increasing source of environment pollution, by substantially enhancing the rate of sales tax on polythene bags from 8% to 30% so that their use is discouraged. This necessitated immediate action.

Since the Legislative Assembly was not in session and amendment in the Himachal Pradesh General Sales Tax Act, 1968, had to be made urgently, the Himachal Pradesh General Sales Tax (Amendment) Ordinance, 1995 (Ordinance No. 4 of 1995) was promulgated under clause (1) of Article 213 of the Constitution of India by the Governor of Himachal Pradesh on 13th of November, 1995, which was published in the Rajpatra, Himachal Pradesh (Extra-ordinary) dated the 15th November, 1995. The said Ordinance is now required to be replaced by a regular enactment.

This Bill seeks to replace the aforesaid Ordinance without any modification.

SANT RAM,  
*Minister-in-charge.*

SHIMLA :

*The 15th January, 1996.*

## FINANCIAL MEMORANDUM

Clauses 2 and 3 of the Bill seek to enhance the rate of tax on polythene bags from 8 per cent to 30 per cent. As a result of this enhancement there will although accrue some income to the State exchequer, yet in view of the State's policy of discouraging the use of polythene bags, there will be loss of Rs. 5.00 lakhs to the State exchequer per annum.

## MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

-Nil-

## RECOMMENDATIONS OF THE GOVERNOR UNDER ARTICLE 207 OF THE CONSTITUTION OF INDIA

[File No. EXN-C (9)2/90-Vol-V]

The Governor of Himachal Pradesh, after having been informed of the subject-matter of the Himachal Pradesh General Sales Tax (Amendment) Bill, 1996, recommends, under Article 207 of the Constitution of India, the introduction and consideration of the aforesaid Bill in the State Legislative Assembly.